भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-2
उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय संबंधी पहल

†*2. श्री बैजयंत पांडा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय संबंधी पहल से दूरस्थ, ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की सुलभता बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इस पहल के प्रारंभ से लेकर अब तक डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से कितने शिक्षार्थियों को नामांकित किया गया है; और
(ग) सरकार द्वारा उक्त पहल के अंतर्गत चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक गुणवत्ता, क्रेडिट अंतरण और उद्योग के लिए इनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय संबंधी पहल” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बैजयंत पांडा द्वारा दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): भारत सरकार ने शिक्षार्थी-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार की है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार ने लचीली और बहु-विषयक अधिगम प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म की स्थापना की परिकल्पना की है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) ने अक्टूबर, 2025 में "नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय (एनडीयू) प्लेटफॉर्म" का शुभारंभ किया है। एनडीयू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा , क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य सीमांत डोमेन आदि जैसे उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में ऑनलाइन तथा मिश्रित कौशल-आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु एक डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ़) के अनुरूप हैं, जिनके सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट्स (एबीसी) में स्थानांतरित किया जाएगा। वर्तमान तिथि के अनुसार, एनडीयू प्लेटफ़ॉर्म पर 100 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनके लिए 2.70 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए कई पहल की हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम एवं ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम, 2020 में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन माध्यमों से गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ढांचा का प्रावधान है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में, 4,26,196 शिक्षार्थियों के नामांकन के साथ 120 से अधिक विश्वविद्यालयों/एचईआई में 800 से अधिक ऑनलाइन कार्यक्रमों को अनुमोदन दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, आईआईटी सहित प्रमुख संस्थान, कृत्रिममेधा, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित डेटा साइंस में ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस कार्यक्रम में 2021 से अब तक 55,000 से अधिक नामांकन हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने के उद्देश्य से, शिक्षा मंत्रालय ने प्रमुख संस्थानों से पाठ्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए स्वयम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म पर 20,000 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान किए गए और इनके लिए इस प्लेटफार्म को शुरू करने के बाद से 6 करोड़ से अधिक संचयी नामांकन हुए हैं। इसके अलावा, यूजीसी (स्वयम के माध्यम से ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2021 के तहत, उच्चतर शैक्षिक संस्थान स्वयम के माध्यम से एक सेमेस्टर में 40% तक क्रेडिट दे सकते हैं। जुलाई 2026 तक, 450 विश्वविद्यालयों ने क्रेडिट ट्रांसफर के लिए स्वयम फ्रेमवर्क को अपनाया है।

इसके अलावा, उद्योग-अकादमिक सहकार्यता बढ़ाने और शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म आरम्भ किया है। जुलाई 2026 तक, यह प्लेटफ़ॉर्म 89 उद्योग भागीदारों के सहयोग से 15 क्षेत्रों में 500 से अधिक उद्योग-अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

*****